

BRICS राष्ट्रों द्वारा अमेरिकी डॉलर के विकल्प पर वचिार

प्रलिमिंस के लयि:

[16वाँ BRICS शखिर सममेलन](#), [ग्लोबल साउथ](#), [SWIFT नेटवरक](#), [सेंट्रल बैंक डजिटिल करेंसी](#), [एकीकृत भुगतान इंटरफेस](#), [भारतीय रजिस्वर बैंक](#), [भारत-UAE स्थानीय मुद्रा नपिटान प्रणाली](#)

मेन्स के लयि:

वैश्वकि व्यापार और वतित पर डी-डॉलरीकरण का प्रभाव, भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, भारत से संबधति और/या भारत के हतिों को प्रभावति करने वाले समूह एवं समझौते, कषेत्रीय एवं वैश्वकि समूह ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

अक्टूबर 2024 में [16वें BRICS शखिर सममेलन](#) में [BRICS देशों](#) ने व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने या अमेरिकी डॉलर पर नरिभरता कम करने के क्रम में एक नई BRICS मुद्रा के संबध में चर्चा की ।

- इसकी प्रतकिरया में अमेरिका के नव-नरिवाचति राष्ट्रपति [डोनाल्ड ट्रंप](#) ने कहा कि यदि BRICS देश वैश्वकि रजिस्वर मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर के स्थान पर कसिी मुद्रा को अपनाते हैं तो उन पर 100% तक आयात शुल्क लगाया जा सकता है ।
- इससे डॉलर पर नरिभरता कम करने के साथ बहुधरुवीय वतिलीय प्रणाली के नरिमाण के संबध में वमिर्श को बढ़ावा मलिा है ।

BRICS देश अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में वैकल्पकि मुद्राओं की तलाश क्यो कर रहे हैं?

- लेन-देन लागत में कमी: स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने से अन्य मध्यस्थ वदिशी मुद्राओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जसिसे लेन-देन लागत कम होने के साथ BRICS देशों के बीच व्यापार और भी अधिक सुलभ हो सकेगा ।
- डॉलर का प्रभुत्व: वर्तमान में वैश्वकि व्यापार का 90% से अधिक अमेरिकी डॉलर द्वारा होता है । अमेरिकी डॉलर पर अधिक नरिभरता से देश [अमेरिकी मॉडरकि नीतियों](#) से काफी प्रभावति होते हैं ।
 - इससे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थकि असंथरिता पैदा होने से यह देश अपनी या अन्य मुद्राओं का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था पर अधिक नरियंत्रण प्राप्त करने हेतु प्रेरति होते हैं ।
 - कई BRICS देश (वशिष रूप से ग्लोबल साउथ के देश) डॉलर जैसी प्रमुख मुद्राओं को पाने के लयि संघर्षरत रहते हैं, जसिसे उनकी वस्तुओं का आयात करने, ऋण चुकाने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की कषमता में बाधा उत्पन्न होती है ।
 - स्थानीय मुद्राओं के उपयोग से न केवल इन चुनौतियों से नपिटा जा सकेगा बल्कि स्थानीय बाजारों के बीच संवृध एवं व्यापार को बढ़ावा मलिगा ।
- राजनीतिक प्रेरणाएँ: स्थानीय मुद्राओं पर वचिार करने का एक प्रमुख कारण अमेरिका द्वारा लगाए गए वतिलीय प्रतबिधों के प्रभाव से बचना है ।
 - उदाहरण के लयि, अमेरिका ने रूस और ईरान को SWIFT (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) नेटवरक से प्रतबिधति कयिा है, जो अंतर्राष्ट्रीय वतिलीय लेनदेन की प्रमुख प्रणाली है, जसिके कारण इन देशों को व्यापार बनाए रखने हेतु विकल्प तलाशने पड़े हैं ।
 - अमेरिकी डॉलर पर नरिभरता कम होने से इन देशों को वैश्वकि व्यापार में अधिक संप्रभुता प्राप्त होने के साथ बहारी आर्थकि दबावों के प्रतबिधति संवेदनशीलता में कमी आएगी ।
- भू-राजनीतिक कारण: ब्राजील, रूस और भारत जैसे देश युआन तथा रूबल जैसी मुद्राओं को बढ़ावा देकर (यहाँ तक कि एकीकृत BRICS मुद्रा पर वचिार करके) अमेरिकी हस्तकषेप से बचने हेतु प्रयासरत हैं ।
 - जैसे-जैसे चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ रही हैं, ये कई देशों के लयि प्रमुख व्यापारकि साझेदार बन रहे हैं । यह बदलाव व्यापार हेतु वैकल्पकि मुद्राओं के उपयोग को प्रेरति करता है ।

स्थानीय मुद्राओं में व्यापार

- **चीन का दृष्टिकोण:** चीन ने द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौतों के माध्यम से अपनी मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दिया है, **जैसा कि इथियोपिया के साथ चीन के व्यापार में देखा गया है।**
 - द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौते का आशय दो केंद्रीय बैंकों के बीच एक वित्तीय अनुबंध से है जिसके तहत एक मुद्रा की एक नश्चिती राशिको दूसरी मुद्रा की समान राशिके साथ वनिमिय कयिा जाता है।
 - चीन के **वस्तु वनिमिय व्यापार मॉडल** के तहत अफ्रीकी देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं के बदले वस्तुओं के आदान-प्रदान को प्राथमिकता देकर पारंपरिक मुद्राओं का उपयोग हतोत्साहित होता है।
 - इन मुद्राओं का उपयोग उन देशों से सामान खरीदने के लिये कयिा जाता है, जनिहें वापस चीन को नरियात कर दयिा जाता है, जसिसे इसके मुद्रा अंतरराष्ट्रीयकरण प्रयासों को समर्थन मलिता है।
- **दक्षिण अफ्रीका:** दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा (**दक्षिण अफ्रीकी रैंड**) का नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और एस्वातनी द्वारा अपनी मुद्राओं के साथ उपयोग करने से न केवल आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मलिता है बल्कि इन देशों की अमेरिकी डॉलर या यूरो पर नरिभरता भी कम होती है।
- **भारत-रूस:** अमेरिकी प्रतबंधों की प्रतिक्रिया में **भारत और रूस द्वारा अपनी स्थानीय मुद्राओं (रुपए एवं रूबल)** को प्रोत्साहन देने के साथ 90% द्विपक्षीय व्यापार अब इन मुद्राओं या वैकल्पिक मुद्राओं में कयिा जाता है।

अमेरिकी डॉलर पर नरिभरता में कमी से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **चीनी प्रभुत्व:** अमेरिकी डॉलर पर नरिभरता कम होने से चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभुत्व को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। चीन वैश्विक व्यापार में, खासतौर पर रूस और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ, युआन के इस्तेमाल को बढ़ाने पर ज़ोर दे रहा है।
 - BRICS में, **चीन की प्रमुख अर्थव्यवस्था असंगत प्रभाव उत्पन्न कर सकती है**, जो संभावित रूप से भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य सदस्यों के हितों को प्रभावित कर सकती है, जो बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणाली चाहते हैं।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** BRICS मुद्रा या स्थानीय मुद्राओं को अपनाने में चुनौतियाँ हैं, जैसा कि **भारत-रूस व्यापार में देखा गया है**, जहाँ अमेरिकी प्रतबंधों से संबंधित बैंकिंग चिंताएँ **बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन** को प्रभावित करती हैं।
 - BRICS की कई मुद्राओं का **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग नहीं कयिा** जाता है, जसिसे स्थानीय मुद्राओं के साथ व्यापार की प्रभावशीलता सीमति हो जाती है।
 - जो देश **आयात की तुलना में नरियात अधिक करते हैं**, उन्हें व्यापार के लिये विदेशी मुद्राएँ संचित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जसिसे स्थानीय मुद्राओं का उपयोग कठिन हो जाता है।
- **तरलता संबंधी मुद्दे:** अमेरिकी डॉलर का व्यापक रूप से उपयोग (तरलता का अधिक होना) कयिा जाता है। वैकल्पिक मुद्राएँ उतनी तरलता प्रदान नहीं कर सकती हैं, जसिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना अधिक कठिन हो जाएगा।
- **अस्थिरता और वनिमिय दर जोखिम:** डॉलर से दूर जाने के दौरान, देशों को **वनिमिय दर में अस्थिरता का अनुभव हो सकता है।**
 - यह बात खासतौर पर उन देशों के लिये है, जनिके **वित्तीय बाज़ार पूरणतः स्थापित नहीं हैं**। ऐसी अस्थिरता वाणज्य, नविश और पूंजी प्रवाह को बाधित कर सकती है, जसिसे आर्थिक अनश्चितता और बढ़ सकती है।

BRICS आयात पर 100% अमेरिकी टैरिफि के संभावित प्रभाव क्या हैं?

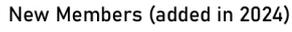
- **वैश्विक व्यापार पर प्रभाव:** ऐसे टैरिफि BRICS देशों को इंटर-ब्लॉक व्यापार को बढ़ाने के लिये मज़बूर कर सकते हैं, जसिसे डी-डॉलराइज़ेशन में तेज़ी आएगी।
- **गैर-अमेरिकी बाज़ारों में आयात विविधीकरण से वैश्विक व्यापार प्रणालियों पर अमेरिकी प्रभाव कम हो सकता है।**
 - इससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, चीनी युआन (रेनमिनिबी) और अन्य गैर-परंपरागत आरक्षित मुद्राओं में वृद्धि हो सकती है, जो बहुध्रुवीय वैश्विक वित्तीय प्रणाली की ओर क्रमिक कदम को दर्शाता है।
 - इस परिवर्तन से **अमेरिकी 'फाइनेंशियल लीवरेज' कम हो जाता है**, लेकिन उभरती मुद्राओं के बीच प्रतस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है।
- **अमेरिका पर प्रभाव:** BRICS देशों से आयात पर 100% टैरिफि लगाने से आयात की लागत में वृद्धि होने के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा।
 - अमेरिका में व्यापार मार्गों में बदलाव देखने को मलि सकता है, जसिसे **आयात संभवतः तीसरे पक्ष के देशों में स्थानांतरित** हो सकता है। इससे घरेलू वनिर्मिाण में वृद्धिकयिे बनिा **अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिये लागत बढ़** सकती है।
 - BRICS देश **अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफि लगाकर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं**, जसिसे व्यापार तनाव मेमे वृद्धि होगी तथा वैश्विक व्यापार गतशीलता प्रभावित होगी।
 - अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व व्यापार में डॉलर की केंद्रीय भूमिका से उत्पन्न हुआ है। वैकल्पिक मुद्राओं को अपनाने से **इसका वित्तीय प्रभाव कम हो सकता है**, जसिसे अमेरिका को विविधतापूर्ण वैश्विक प्रणाली को अपनाने के लिये मज़बूर होना पड़ सकता है।

BRICS

Initial Members

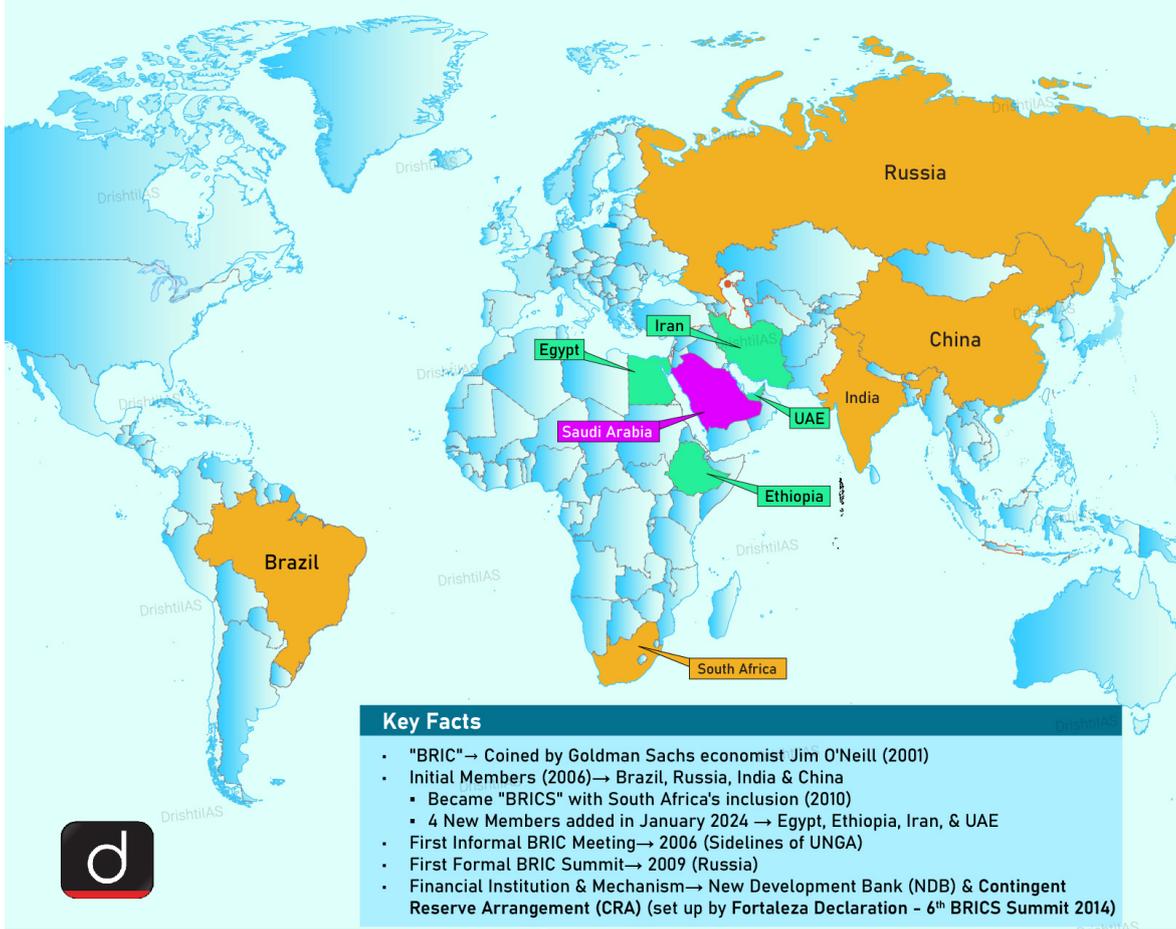


New Members (added in 2024)



Invited to join BRICS (not an Official Member yet)

DrishTiIAS



अमेरिकी डॉलर पर नरिभरता कम करने के लिये भारत की कौन-सी पहल है?

- रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण: वर्ष 2022 में, [भारतीय रजिर्व बैंक \(RBI\)](#) द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिये, विशेष रूप से रूस जैसे देशों के साथ भारतीय रुपए में चालान और भुगतान की अनुमति प्रदान की गई।
 - यह कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया था, जिसका उद्देश्य डॉलर पर नरिभरता कम करना था।
 - UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उद्देश्य [रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण](#) करना है।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

अर्थ

- सीमा पार हस्तांतरण में भारतीय रुपए के उपयोग में वृद्धि करना

इसमें शामिल है

- आयात और निर्यात के लिये रुपए का उपयोग
- चालू और पूंजी खाता हस्तांतरण के लिये रुपए का उपयोग

भारतीय रुपया चालू खाते में पूरी तरह से लेकिन पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है।

आवश्यकता

- अमेरिका द्वारा अमेरिकी डॉलर का हथियारीकरण (प्रतिबंधों के लिये)
- डी-डॉलराइजेशन की लहर
- चीनी मुद्रा रॉम्बिनी का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीयकरण
- वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार कारोबार में भारत की न्यूनतम हिस्सेदारी (1.7%)

RBI के प्रयास

- सीमा-पार व्यापार में भारतीय मुद्रा - विदेश व्यापार नीति 2023 में प्रमुख घटक
- 18 देशों के साथ रुपए में व्यापार समझौते हेतु तंत्र प्रस्तुत किया गया
 - इन देशों के बैंकों को विशेष चोस्ट्रो रुपया खाते (SVRAs) खोलने की अनुमति दी गई
- "भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता" पर परिपत्र (2022)
- भारतीय रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार को सक्षम बनाया गया

महत्त्व

- अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भरता
- विदेशी मुद्रा भंडार रखने की कम आवश्यकता
- भारतीय व्यापार की बेहतर सौदा निपटान शक्ति
- मुद्रा की अस्थिरता का कम जोखिम

चुनौतियाँ

- रुपया का पूरी तरह से परिवर्तनीय न होना
- अन्य देशों को भारतीय रुपया (INR) रखने की कम आवश्यकता; वैश्विक निर्यात में भारत की कम हिस्सेदारी
- बाह्य आघातों के प्रति रुपया और अधिक संवेदनशील हो सकता है
- रुपए की आपूर्ति पर भारत का कम नियंत्रण

उठाए जा सकने योग्य कदम

- INR में अधिक उदारीकृत निपटान (भारत और विदेशों में)
- भारत को वैश्विक वित्तीय बाजार में अपनी पहुंच का विस्तार करना चाहिये
- व्यापार घाटे को कम करने के लिये निर्यात-उन्मुख अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होना



- द्विपक्षीय व्यापार समझौते:** भारत सक्रिय रूप से द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर संवाद कर रहा है, जिसमें स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि भारत-यूएई स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली।
 - यह रणनीतिक कदम आर्थिक स्वायत्तता बढ़ाने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
- विदेशी मुद्रा भंडार:** RBI यूरो और येन जैसी अन्य प्रमुख मुद्राओं को शामिल करके अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता ला रहा है, तथा अमेरिकी डॉलर के हिस्से को कम कर रहा है।

आगे की राह:

- भारत की संतुलित कूटनीति:** भारत को कूटनीतिक रूप से अमेरिका के साथ जुड़ना चाहिये, तथा इस बात पर बल देना चाहिये कि व्यापार तंत्र में विविधता लाने का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता है, न कि डॉलर को प्रतिस्थापित करने के उपाय।
 - अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती आर्थिक साझेदारी पर प्रकाश डालने से चिंताओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
 - केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को अपनाने में तेजी लाने और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) जैसे प्लेटफार्मों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है।
 - इसके अतिरिक्त, भारत को BRICS देशों के साथ मलिकर कार्य करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय सुधार उसके दीर्घकालिक आर्थिक हितों के अनुरूप हों तथा BRICS देशों में भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करके व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिये तंत्र विकसित किया जाए।
- डिजिटल भुगतान समाधान:** मुद्रा मांग को कुशलतापूर्वक संतुलित करने, लागत कम करने और स्थानीय मुद्रा व्यापार की सफलता सुनिश्चित करने के लिये एक विश्वसनीय, डिजिटल भुगतान प्रणाली आवश्यक है।
- वृद्धिशील प्रगति:** जटिलताओं को देखते हुए, करमिक दृष्टिकोण सबसे अधिक व्यावहार्य प्रतीत होता है। देशों को स्थानीय मुद्राओं में कुछ व्यापार करके शुरुआत करनी चाहिये, धीरे-धीरे सिस्टम का विस्तार करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे और विश्वास का निर्माण करना चाहिये।

प्रश्न: वैश्विक वृत्ति को नया आकार प्रदान करने में BRICS की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'डी-डॉलराइजेशन' के नहितार्थों पर चर्चा कीजिये। भारत के लिये चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न (PYQ)

प्रलिमिस

प्रश्न रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? (2015)

- (a) रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना
- (b) रुपए के मूल्य को बाज़ार की शक्तियों द्वारा नरिधारति होने देना
- (c) रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना
- (d) भारत में मुद्राओं के लिये अंतरराष्ट्रीय बाज़ार वकिसति करना

उत्तर: (c)

प्रश्न. BRICS के रूप में ज्ञात देशों के समूह के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजिये: (2014)

1. BRICS का पहला शखिर सम्मेलन वर्ष 2009 में रओ डी जेनेरयो में हुआ था।
2. दकषणि अफ्रीका BRICS समूह में शामिल होने वाला अंतमि देश था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (b)